भारत में जन दूध के महत्व का बचाव करना

कर्नाटक दुग्ध फेडरेशन अपेने दुग्ध संग्रह केंद्र, जिसका फैलाव गांव–गांव तक है, के जरिए पूरे राज्य में छोटे दुग्ध उत्पादकों के सतत आय को बढाने में सक्षम है (फोटो ग्रेन)

GRAIN

''हम गाय का ख्याल रखते हैं और
गाय हम लोगों का ख्याल रखती है।''

तमिलनाडु के थालावाडी के एक किसान मारायल ने कहा। उसकी दो गायें प्रत्येक दिन 6 से 10 लीटर दूध देती हैं, जिसे वह 30 से 40 सेंट प्रति लीटर बेचती है।

पूरे भारत में देश में लाखों दुग्ध उत्पादक किसान है। इनमें से प्रत्येक के पास एक या दो गायों का मालिकाना है, और ये किसान लाखों से भी ज्यादा परिवारों को और सैकड़ों ... हजारों की संख्या में असंगठित दुग्ध डेयरी और चाय के दुकानों को दूध की आर्पूति करते हैं। ये सारे छोटे-छोटे अपंजीकृत ईकाईयां इन्हीं छोटे किसानों से सीधे-सीधे दूध खरीदती पसंद करती हैं जो ताजा दूध कम कीमत पर उपलब्ध कराते हैं।

भारत में 70 मिलियन ग्रामीण घरों में जो कि समस्त ग्रामीण परिवारों की संख्या के आधी हैं... अपने घरों में दूध देने वाले मवेशी रखते हैं। इनमें से आधा दूध जिसका वो उत्पादन करते हैं, भैंस का दूध होता है, जिसे वे उसी समुदाय में चराते हैं जहां उनका निवास स्थान होता है। जबकी इनमें से एक चौथाई हिस्से का वे स्थानीय स्तर पर योग हर्टस, घी (परिशोधित मक्खन) और दूसरे दूध उत्पादों के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

भारत के दुग्ध उत्पादन उधोग में 90 मिलियन लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जिनमें से 75 मिलियन महिलायें हैं। यह छोटे और सीमांत किसानों, भूमीहीन गरीबों और लाखों ग्रामीण आबादी के लिए आय सर्जन का महत्वपूर्ण जरीया है। और यह अभी भी भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रक्षेत्र है जो कि कुल कृषि जीडीपी का 22 फीसदी योगदान देता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है जो कि विश्व के कुल दूध उत्पादन में 15 फीसदी का योगदान देता है। दूध भारतीय खानपान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगभग 108 मिलियन टन वार्षिक रूप से उत्पादित होने वाला दूध घरेलू स्तर पर ही खपत कर लिया जाता है। ''श्वेत क्रांति'' के अंर्तगत भारत के डेयरी सहकारिता के जरिये दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 1980 से 2006 के बीच दुग्ध उत्पादन में तिगुणा से ज्यादा बढ़ोतरी देखी गयी। लेकिन दुग्ध उत्पादन के लिहाज से महत्वपूर्ण प्रगति जनता से जुड़ी है जो कि राष्ट्रीय दुग्ध बाजार का 85 फीसदी तक पहुंचता है। उन दिनों में भारत के छोटे किसान और घरेलू बाजार जो कि देश में दुग्ध उत्पादन के लिहाज से व्यापक विस्तार की दृष्टि से वास्तविक आधार प्रदान किया, और इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में आये इस बढ़ोतरी का व्यापक लाभ हुआ।

1980 और 1990 के बीच राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने देश में दुग्ध उत्पादन और खपत में बढ़ोतरी के लिए इस दौरान इस कार्यक्रम का दूसरा और तीसरा चरण लागू किया। ऑपरेषन फलड का प्रमुख लक्ष्य भारतीय गांवो के दूध उत्पादन कर्ताओं को षहरी बाजार से जोड़कर पोषण में सुधार और गरीबी में कमी लाना था।

जनता के दुग्ध उत्पादन में कॉरपोरेट का दखल

लेकिन भारतीय दूध उत्पादन क्षेत्र को हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और जिसतरह का दिशा मुक्त व्यापार समझौतों जैसे कि इंडिया -ईयू एफ टी यू के तहत जिस तरह के

टेबल 1: चुनिंदा देशों में राष्ट्रीय दुग्ध बाजार में गैरपरंपरागत दूध उत्पादकों की हिस्सेदारी

देश	जन दूध उत्पादकों द्वारा राष्ट्रीय दूध उत्पादन में हिस्सेदारी का प्रतिशत
सभी विकासशील देशों में	80
अर्जेन्टिना	15
बांग्लादेश	97
ब्राजील	40
कोलंबिया	83
भारत	85
केन्या	86
मेक्सिको	41
पाकिस्तान	96
पराग्युवे	70
रवांडा	96
श्रीलंका	53
यूगांडा	70
उरुग्वे	60**
जांबिया	78

***मानव विकास सूचकांक के अनुसार विश्व के 85 फीसदी जनसंख्या विकासशील देशों में रहती है**
****यह आँकड़ा सिर्फ चीज के लिए है।**

स्रोतः ग्रेन

समझौते किये गये उसने इस रास्ते को और जटिल बनाया है। जब पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था संकट में है ऐसे में भारत बड़े बहुदेशीय कॉरपोरेट घरानों के लिए संभावित रूप से महत्वपूर्ण बन गया है। इंडिया -ईयू एफ टी यू जरूरी तौर पर बड़े कॉरपोरेषनों का प्रतिनिधित्व करता है।

इयूकोलेट जो कि यूरोप के डेयरी उधोग और व्यापार से जुड़ी प्रमुख प्रतिनिधिक संस्था है ने यूरोपियन यूनियन के समझौताकारों पर इस बात के लिए दबाव बनाया है कि भारत के साथ होने वाली बातचीत में इस

बात पर जोर दें कि भारत यूरोपियन यूनियन को भी उस तरह की सुविधायें दे जैसी सुविधा भारत दूसरे देशों को देता है। दिसंबर 2011 के अपने वक्तव्य में इयूकोलेट ने इस तथ्य को रेखांकित किया भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उपभोक्ता है, और भारत दुग्ध का नियमित आयातक हो सकता है। कंपनी के द्वारा यह कहा गया कि यूरोपीय संघ को समझौतों में दृढता दिखाना चाहिए और यूरोपिय कंपनियों के लिए भारत के दुग्ध उपभोक्ता के रूप में बेहतर बाजार का विस्तार की तरफ कदम बढाना चाहिए।

इन सब के विपरित भारत में सरकार को छोटे-छोटे दुग्ध उत्पादक कृषकों के हित को संरक्षित करने के लिए सरकार की तरफ से पर्याप्त और पुख्ता कदम उठाये जाने की जरूरत है। अप्रैल 2013 में एक संसदीय पैनल ने संसद की कृषि समिति की बैठक में इस समिति के सदस्यों ने यह कहा कि देश के दुग्ध उत्पादकों के हितों को एकतरफा व्यापार और बड़े व्यापारियों के भेदभाव पूर्ण और एकपक्षीय नीतियों से बचाया जाना चाहिए। देश के किसान आंदोलनों की तरफ से भी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाले विदेशी व्यापार समझौतों को जबरदस्त दबाव है जिसकी वजह से देश में और ज्यादा उदारीकरण आयेगा और देश के कृषि उधोग क्षेत्र और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को गहरा नुकसान पहुंचेगा।

पहले से ही यह ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि भारत के दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ रहा है, विषेष रूप से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में लिये गये उस निर्णय के बाद जिसके विदेशी खुदरा व्यापारियों को भारत में मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 फीसदी हिस्सेदारी और एकल ब्रांड रिटेल में 100फीसदी निवेश की अनुमती दी गयी। रोबोबैंक के केविन बेलामी के अनुसार, जो कि भारत के सबसे बड़े कृषि व्यापार में निवेश करने वाली कंपनी है के मुताबिक यह उस दिशा में पहला कदम है जिसके तहत बाहर के डेयरी उत्पादों को भारतीय बाजार में उतारा जाना है।

रिटेल के क्षेत्र में विदेशी निवेश को लेकर हुए विरोध को देखते हुए भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 2012 में रिटेल के क्षेत्र में विदेशी निवेश को लेकर अंतिम फेसला लेने का अधिकार राज्य की सरकारों पर छोड़ दिया। कुल मिलाकर देश की 30 राज्य सरकारों में से केवल 10 राज्य की सरकारों ने ही कहा है कि वे पूरी तरह से विदेशी निवेश को आंमंत्रित किये जाने को लेकर लिये गये नीतिगत निर्णय के साथ है, जबकि 7 राज्यों ने इसका विरोध किया और बाकी राज्यों को इसके संबंध में अभी निर्णय लेना बाकी है। राज्य सरकारों का निर्णय राज्य में डेयरी कॉपोरेटिव सोसाईटी की स्थिति के अनुरूप है। राज्य सरकारें जैसे कर्नाटक, वहां दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सरकार की भागीदारी बहुत ज्यादा है, जो कि सरकार को प्राप्त कर का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुग्ध उत्पादन के व्यापार से आता है।

भारत के दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में सहकारिता की भूमिका

कर्नाटक उन राज्यों में से एक महत्वपूर्ण राज्य है जहां दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता की भूमिका अहम है। कर्नाटक मिल्क फेडरेषन केएमएफ दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सहकारिता दुग्ध फेडरेषन है, जिस पर कर्नाटक राज्य के छोटे-छोटे व्यापारियों का मालिकाना हक होने

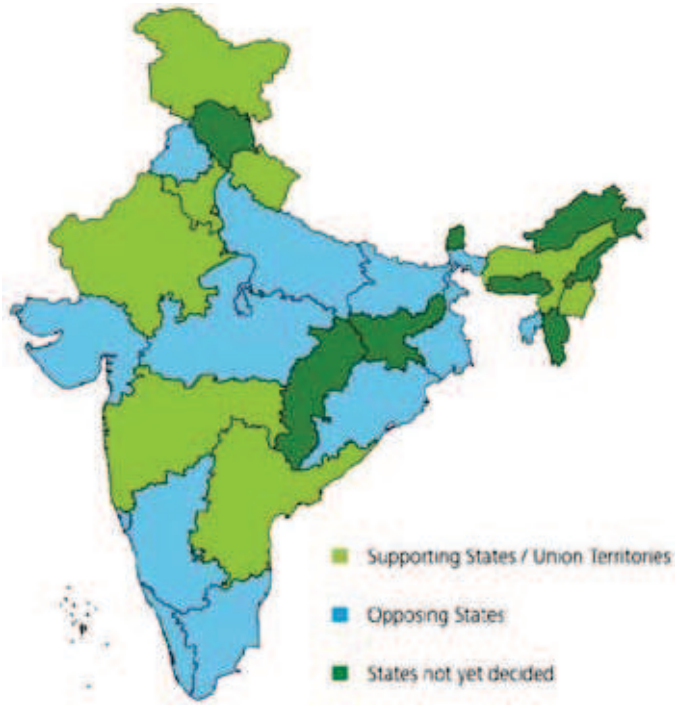

के साथ ही इसका प्रबंधन भी कर्नाटक राज्य के दुग्ध उत्पादकों के द्वारा किया जाता है। केएमएफ के पास 2.23 मिलियन दूध उत्पादक हैं, जो कि राज्य के 13 जिलों के जिला सहकारिता दुग्ध यूनियन से जुड़े हुए हैं और इसके अंर्तगत 12,066 सहकारिता सोसाईटी ग्राम स्तर पर काम कर रही हैं।

चमराज नगर का एक जिला स्तर की सहकारिता ईकाई में प्राथमिक स्तर के 225 सहकारी ईकाईयों के जरिए 85,000 से 90,000 हजार लीटर दूध प्रत्येक दिन एकत्रित किया जाता है। 60 दुग्ध संग्रह केंद्र जो कि औसतन पाँच गॉवों पर बनाए गए एक दुग्ध संग्रह केंद्र के जरिए दिन में दो बार दूध एकत्रित किया जाता है, उसके पष्चात चमराजनगर षहर में बने दूध षीत केंद्रो पर भेजा जाता है। जिले में तीन बड़े दूध षीत टेंक लगाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक की क्षमता 30,000 हजार लीटर प्रति केंद्र है। जो किसान इन सहकारी केंद्रो में दूध देते हैं उन्हें प्रत्येक लीटर 7 से 21 रुपया (11-34 सेंट) तक प्राप्त होता है। इसका निर्धारण प्रत्येक संग्रह केंद्रो पर लगाए गये लैक्टो मीटर जिसके जरिए दूध में वसा की मात्रा की जाँच होती है के आधार पर होता है। सहकारी केंद्रों द्वारा प्राप्त दूध में जो औसतन वसा की मात्रा पाई जाती है वह 8.4 फीसदी है। इसके बाद दूध को 1 लीटर से लेकर 2.5 लीटर के पैकेट में बेचने के लिए पैक किया जाता है। कर्नाटकर मिल्क फेडरेषन इस दूध को उपभोक्ताओं को 32 रूपए प्रति लीटर (50) सेंट के दर से बेचता है।

कर्नाटक प्रत्येक वर्ष 5 मिलियन लीटर दूध पैदा करता है, जो कि कर्नाटक के कुल दूध खपत से 3 मिलियन लीटर ज्यादा है। बाकी बचे दूध को एसकेए डेयरी फूड जो कि एक निजी कंपनी है और इसे टेंडर की प्रक्रिया अपनाकर सरकार द्वारा अनुबंधित किया गया है के जरिए प्रसंस्करित कर दूध पाउडर (स्किम दूध पाउडर और संपूर्ण दूध पाउडर) तैयार किया जाता है। सहकारी समिति द्वारा एसकेए को प्रति लीटर 2.5 पैसा भुगतान किया जाता है(100 पैसे बराबर1 रुपया।) चमराजनगर के सहकारी समितियों की दूध पाउडर भंडारण की क्षमता बहुत ज्यादा

''हमारा दुग्ध उत्पादक किसान बनने की कोई धारणा नहीं है, लेकिन यह हमारे जीवन का हिस्सा है।''अपने घर के पीछे डेयरी चलाने वाली मारयाल और उनके पति जैसे लोग ही देश में डेयरी उत्पादन के वृहत्तर विस्तार का वास्तविक आधार हैं। (फोटोः ग्रेन)

अर्थात 85 हजार किलोग्राम है। दूध पाउडर की कीमत दूध की कीमतों के 10 गुणा है इसलिए सहकारी समितियों के लिए यह घी के साथ बड़ा उत्पाद है। उत्पादित दूध पाउडर के एक हिस्से को कर्नाटक सरकार द्वारा अपने स्कूल के बच्चों को फूड सब्सिडी कार्यक्रम के तहत दिया जाता है। इस कार्यक्रम कें अंर्तगत 1 से 6 कक्षा के बच्चों को स्किम दूध पाउडर और 7-10 कक्षा के बच्चों को संपूर्ण दूध पाउडर दिया जाता है। बाकी के बचे दूध को अन्य राज्यों जैसे कि तमिलनाडु यहां तक की दिल्ली को बेचा जाता है। यह राज्य के लिए आय का एक बहुत बड़ा जरिया है।

कर्नाटक के गांवों में अपने व्यापक पहुँच के जरिए केएमएफ पूरे राज्यों मे छोटे-छोटे दूध उत्पादकों के लिए सतत रूप से आमदनी का जरिया बन गया है। ऐसा नहीं है कि सहकारी व्यवस्था में कमियाँ नहीं है। किसानों को भुगतान में देरी एक बहुत बड़ी और आम समस्या है। उत्पादकों को प्रत्येक सप्ताह भुगतान किया जना है, लेकिन राजराजेश्वर नगर के एक किसान ने बताया कि भुगतान होने में एक माह से भी ज्यादा लग जाता है। सहकारी संगठनों के विभिन्न स्तरों पर यहां तक की सदस्यों के बीच भी वित्तिय पारदर्षिता भी एक अहम मुद्दा है। नीचले स्तर के सहकारी समितियों का केवल एक प्रतिनिधि ही उपर के स्तर पर भाग लेता है।

कर्नाटक कोऑपरेटिव एवं दूसरे सहकारी संगठनों के पास सीधे-सीधे किसानों से दूध संग्रह करने और उसे बाजार तक लाने की व्यापक क्षमता है। इसके विपरित बड़ी डेयरी कंपनियों का ऐसा करने में बहुत ही कम रूची है। इसके बदले ज्यादातर डेयरी कंपनियाँ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरोप एंव न्यूजीलैंड से पाउडर का आयात करती हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच विदेशी व्यापार समझौते के विरोध करने में कोऑपरेटिव ने भी अहम भूमिका निभाई है। गुजरात की एक बड़ी दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति अमूल ने वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिख कर इस बात पर कड़ा विरोध जताया की दुग्ध उत्पादों के आयात शुल्क पर किसी भी तरह की सुविधा नहीं दिया जाना चाहिए।

दूध और भारत की खाद्य संप्रभुता

मारायल कहती हैं कि ''हमारा दुग्ध उत्पादक किसान बनने की कोई धारणा नहीं है, लेकिन यह हमारे जीवन का हिस्सा है।'' उनके जैसे किसानों के लिए गाय और भैंस क्रमबद्ध और सतत आय का जरिया मुहैया कराती हैं। छोटे-छोटे दुग्ध उत्पादकों और दुग्ध सहकारी समितियों का उत्कृष्ट संजाल भारत के दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को एक सशक्त मॉडल बनाता है, जिसे कि अब मुक्त व्यापार समझौतों और उदारवादी निवेश नीतियों से खतरा पैदा हो गया है।

यूरोपियन यूनियन से व्यापक तौर पर सब्सिडी वाले दूध पाउडर एवं अन्य दूध उत्पादों को आयात के जरिए उपलब्धता सुनिश्चित कराने से प्रसंस्करण करने वालों और खुदरा विक्रेताओं पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध दूध की कीमतों में गिरावट का दबाव होगा, और इसकी वजह से किसान दूध उत्पादन में आई लागत से कम पर अपने उत्पाद बेचने को मजबूर होंगे।

यही कारण है कि भारतीय किसान, सहकारी समितियाँ और ट्रेड यूनियन पिछले कई वर्षों से यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौतों का बढ़चढ़कर विरोध कर रहे हैं। वे इस बात को समझते हैं कि उच्च आयात दर समय की माँग है। उपभोक्ताओं पर अत्यधिक कीमत का दबाव पड़ने से ज्यादा ऐसे प्रतिबंधों के जरिए बड़े उत्पादकों को वैक्लिपक सस्ता और प्रसंस्करित दूध उत्पादों-यहां तक गैर दूध उत्पादों-को सही दूध उत्पादों की कीमत पर थोपे जाने से बचाने के लिए जरूरी है।

निवेशक और डेयरी क्षेत्र के बड़ी व्यापारिक कंपनियाँ भारत और पूरे दक्षिण के दुग्ध बाजार को अपने चपेट में लेने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। भारत में अपने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हित को साधने के साथ ही कारगिल चीन में बड़े डेयरी फार्म स्थ ापित करने के लिए सैकड़ों मिलियन खर्च कर रहा है। फौंटेरा भी चीन और ब्राजील में

बाक्स 1. बड़े दुग्ध उत्पादन ईकाईयों के लिए रास्ता बनाना

भारत में लागू की जाने वाली नयी एफडीआई और व्यापार की नीतियों के जरिए न केवल भारत में दुग्ध का आयात के लिए खुल जायेगा बल्कि वे स्थानीय दुग्ध उत्पादन और प्रसंस्करणाा के व्यापार पर भी कब्जा कर लेंगी। वर्ष 2011 में अमेरिका की बड़ी निजी इक्विटी फार्म ने तिरूमाला दुग्ध उत्पाद में 20 फीसदी हिस्सेदारी खरीद लिया। निजी कंपनी तिरूमाला जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु मे अपने नेटवर्क के जरिएं 1.2 मिलियन लीटर दुग्ध रोजाना एकत्रित करती है और बेचती है। एक साल बाद फ्रेंच की दुग्ध क्षेत्र की बड़ी कंपनी डेनोन ने तिरूमाला में नियंत्रक हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता करना शुरू किया। उसी वर्ष रेबोबैंक ने अपने भारतीय एग्री बिजनेस फंड के जरिए महाराष्ट्र के प्रभात डेयरी में 18.5 मिलियन की इक्विटी निवेा किया। अगस्त 2013 में रेबोबैंक ने अलग से 12 मिलियन डॉलर का निवेश प्रभात में किया जबकि फ्रेंच डेवलपमेंट फायनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोपारकों ने 9 मिलियन डॉलर का निवेश किया।

दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में किया जा रहा यह निवेश उन लक्ष्यों से प्रेरित है जिसके तहत खाद्य क्षेत्र में व्यापक विदेशी निवेश किया जाना है। मैक्डोनाल्ड जैसी कंपनी ने जैसे ही भारत में प्रवेश किया वैसे ही उनके मुख्य वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया। 1990 के आखिरी वर्षों में जब मैक्डोनाल्ड ने भारत में अपने रेस्टोरेंट खोलना शुरू किया था, उनके मुख्य दुग्ध आपूर्तिकर्ता श्रेईबेर फूड्स ने गोयनका जैसे धनी परिवारों के साथ साझेदारी विकसित कर एक बड़ा दुग्ध प्रसंस्करण इकाई महाराष्ट्र में लगाई जो कि अब श्रेईबेर डायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है।

कंपनी ने ठेके पर खेती की व्यवस्था स्थापित की और स्थानिय किसानों से दुग्ध एकत्र करने के लिए एकत्रिकरण केंद्र कलेक्शन सेंटर भी स्थापित किया बल्कि इसके साथ ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े-बड़े ईकाईं भी स्थापित किया। नवंबर 2010 में इस कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से पुणे जिले के 120 एकड़ जमीन में 6000 गायों के लिए '' फयूचर रेडी'' डेयरी फार्म की शुरुआत की। डॉयनेमिक्स ने डेनोन, नेस्ले, यूम और केंटुकी फ्रायड चिकेन को भी आपूर्ति किया। फरवरी 2013 में श्रेईबर-डॉयनेमिक्स से जुड़ी हुई दुग्ध उत्पादन कंपनी इंडोकॉन एग्रो और अलाईड एक्टिविटिज प्राईवेट लिमिटेड में नेस्ले ने 26 फीसदी हिस्सेदारी खरीदकर प्रत्यक्ष निवेश किया। ये कंपनियाँ पश्चिमी भारत में दुग्ध संग्रहण के काम से जुड़ी हुई है।

निजी दुग्ध कंपनियों के बीच जो प्रचलित ट्रेंड दिख रहा है उससे साफ है कि वे साफ तौर पर समेकित रूप से दुध आर्पूति चेन बनाने की दिशा में बढ़ रही हैं जिसके तहत वे बड़े-बड़े फार्म की शुरुआत करती दिख रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादन कंपनी फौनटेरा का इंडियन फार्मर फर्ीलाईजर को ऑपरेटिव इफको और भारतीय वित्तिय कंपनी ग्लोबल डेयरी हेल्थ जीडीएच के साथ एक संयुक्त उद्यम हैं जिसके तहत आंध्र प्रदेश के नजदीक नेल्लोर में ईफको स्पेषल इकोनॉमिक जोन में 65 हेक्टेयर भूमी में 13,000 गायों के लिए डेयरी फार्म स्थापित किया जाना है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब इस परियोजना को अभी रोक दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आंध्रप्रदेश के पशुपालन विभाग ने न्यूजीलैंड से उच्च गुणवत्ता वाले 9000 गर्भवती गायों के आयात किये जाने वाले कंपनी के दरखास्त को खारिज कर दिया। लेकिन इसके लिए मास्टर प्लान को वर्ष 2012 में अनुमती दी गयी थी और जीडीएच के कल्याण चक्रवर्ती को को इसके लिए कार्यकारी निदेशक बनाया गया था।

निजी डेयरी कंपनियां उच्च एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करती है, ये अपना खुद का विशालकाय फार्म स्थापित कर इसकी शरुआत करती हैं (फोटोः कंपास इंडिया)

जीडीएच का दूसरे ईलाकों में भी बड़े दुग्ध उत्पादन परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है दिसंबर 2010 में इसके द्वारा दिये गये प्रेजेन्टेशन में यह बताया गया है कि वह तीन बड़े फार्म प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा था : एक नेल्लोर में इफको इफको और फौटेरा के साथ मिलकर, दूसरा बैंग्लोर में 3500 गायों का 'रणनीतिक रूप से स्थानीय साझेदार'' के साथ जिसमें वर्ष 2011 में परिचालन् ारू किये जाने का लक्ष्य था, और उड़ीसा की सीमा पर आंध्रप्रदेश के उत्तरी तटवर्ती ईलाकों में स्थानीय साझीदार के साथ मिलकर परियोजना् ारू किये जाने की योजना थी।

अनाज व्यापारी कॉरपोरेषन कारगिल की भी भारत के दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना है। वर्ष 2010 में कारगिल की तरफ से घोषणा की गयी कि यह अपने हेज फंड बलैक रिवर असेट प्रबंधन के जरिए चीन और भारत में दुग्ध उत्पादन फार्म में निवेश करेगा। आगे चलकर वर्ष 2012 में ब्लैक रिवर की अनुषंगी ईकाईं कारगिल वेंचर ने भारत के दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पहला निवेश किया। इसने 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर 800 मिलियन भारतीय रूपये का निवे आंध्रप्रदेश के नेल्लोर में स्थित डोडला डेयरी में किया। डोडला ने शुरुआत में भारतीय निजी इक्विटी कंपनी वेचूरेस्ट में निवेश किया था।

तेजी से विस्तार कर रहा है। अगर वे सफल हो जाते हैं तो इसका परिणाम लाखों लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक आपदा के रूप में सामने आयेगा।

लेकिन अन्य जगहों से प्राप्त अनुभव यह बताते हैं कि जनता का दूध सफलता पूर्वक अपने रास्ते में आने वाले रूकावटों का प्रतिरोध करने में सक्षम है। कोलंबिया में छोटे दूध उत्पादक, वेंडर और उपभोक्ताओं ने गंठबंधन कर जन दूध- लेचे पोपुलर-को कानूनी और आवश्यक मानने के लिए सरकार को बाध्य किया। यह सफलता उन्हें तीन तर्कों के आधार पर मिली। पहला, जनता का दूध वर्तमान में जनता की दूध संबंधी जरूरत को पूरा करता है, और बड़े डेयरी फार्म इसकी जगह नहीं ले सकते। दुसरा, लाखों लोगों की जीविका छोटे-छोटे दूध उत्पादन पर निर्भर है, यहाँ भी बड़ी कंपनियाँ कोई विकल्प नहीं सुझातीं। और अंत में, जन दूध की व्यवस्था लोगों को सुरक्षित, ताजा और पोषण युक्त दूध उचित दर पर लाखों घरों को मुहैया कराती हैं।

इस व्यवस्था को भारत, कोलंबिया एवं अन्य जगहों पर भी खाद्य संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। दूध को अवश्य ही जनता के हाँथों में ही होना चाहिए।

ग्रेन 'साउथ इंडियन कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ फारमर्स' मूवमेंट और केनैइयन सुब्रण्यम के इस पब्लिकेशन में सहयोग एवं एकजुटता को महत्वपूर्ण मानता है।

बॉक्स 2. लोगों की चिंता, बड़ा व्यापार नहीं: वास्तविक दुग्ध उत्पादन की

लाईनस जयतीलेक, श्रीलंकाई दुग्ध उत्पादक किसानों का राष्ट्रीय अभियान

श्रीलंका में दुग्ध उत्पादन में लोगों की भागीदारी अभी भी लगभग 53 फीसदी है। अगर श्रीलंकाई सरकार दुग्ध उत्पादन के अपने राष्ट्रीय नीति में सततता बनाए रखती है तो उन्हें तुरंत ही दूध पाउडर के आयात को बंद कर देना चाहिए। बच्चे और बीमार लोगों के लिए षुद्ध दूध उत्पादन को स्थानीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अविलंब कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। यहां तक की इस बात का सुझाव भी दिया जा सकता है कि दूध पर नियंत्रण रखा जाए जबतक हम उत्पादन के लिहाज से बेहतर स्थिति में नहीं पहुंच जाते हैं।

विदेशी गायों और जेनेटिक संसाधनों के आयात को अविलंब समाप्त किया जाना चाहिए। बछड़ों के (चाहे गाय हो या भैंस) की उपलब्ध संख्या को सही तरीके से खानपान और उनके रखरखाव को बेहतर बनाने की जरूरत है- ऐसा करके पुख्ता तरीके से नयी शुरुआत की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। यहां तक की भारत से बॉस इंडिकस ब्रीड का आयात भी नहीं किया जाना चाहिए। कई तरह के हाईब्रीड जानवर दूध के लिए साहीवाल और गिर और सूखे के लिए खिलाड़ी जैसे जानवर श्रीलंका में हैं।

श्रीलंका की बॉस इंडिकस गाय कम से कम 5 बॉतल दूध (1 बोतल में 750 एमएल) या इससे भी ज्यादा दूध देती है। जानवर विभिन्न तरह के घास और चारे पर फलफूल सकते हैं। किसी भी प्रकार के विशिष्ट खानपान की आवश्यकता नहीं है। इस लिहाज से यह दूध उत्पादन का सस्ता और सुलभ जरिया है जो कि क्रीम और प्रोटीन से भरपूर है। भैंस की संख्या चाहे भारतीय हो या स्थानीय दोनों तरह के भैंसो को बढ़ाये जाने की जरूरत है। श्रीलंकाई बॉस इंडिकस प्रजाति को समेकित कृषि विकास खेत जोतने और ग्रामीण यातायात के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गाय का गोबर और मूत्र मिट्टी को उपजाउ बनाने, और उसके संरक्षण का बहुत ही बेहतर जरिया है। भारतीय किसान इसे जीवा अमृत-धन का स्रोत पुकारते हैं- और किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसकी उपजाउ मिट्टी, स्वस्थ पौधों और स्वस्थ मानव पर निर्भर करता है।

तस्वीर केसी नेगी....भारतीय उपमहाद्वीप की देशी प्रजाति सबसे ज्यादा उत्पादक है।

लोगों के लिए दुग्ध उत्पादन गरीबी उन्मूलन के साथ ही बेहतर स्वास्थय का जरिया भी है। इसके जरिए जीविकोपार्जन के साथ ही सुरक्षित, सस्ता सुलभ पोषक भोजन प्राप्त होता है। इस क्षेत्र से की गयी कमाई का समान रूप से और सतत रूप से पूरे क्षेत्र में वितरण होता है। जनता के दुग्ध उत्पादन से प्रत्येक व्यक्ति को लाभ है, सिर्फ बड़े व्यापारिक घरानों को छोड़कर। और यही कारण है कि इसे समाप्त करने को लेकर इस तरह का दबाव है। आखिर बड़े व्यापारियों के पास देने के लिए क्या है? ताजा और उच्च गुणवत्ता दुग्ध उत्पादन और आर्पूति के बदले जो कि सतत रूप से चलते रहता है, के बदले हमें बड़े डेयरी फार्म में उत्पादित, परिशोधित और प्रदूषित दूध सभी तरह के पैकेटों में रिवर एसेट मैंनेजमेंट द्वारा दुगुनी कीमत पर बेचा जाता है। आगे चलकर 2012 में ब्लैक रिवर की अनुशांगी ईकाई कारगिल वेंचर ने अपना पहला निवेश भारतीय दुग्ध क्षेत्र में किया। इसने 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर (800 मिलियन भारतीय रुपये) का निवेश डोडला डेयरी में किया। यह भी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में ही अवस्थित है। डोडला ने शुरुआत में भारत निजी इक्विटी इकाई वेंचररिस्ट में निवेश किया था।

ग्रेन

ग्रेन एक छोटा अंतरर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो कि छोटे किसानों और सामाजिक आंदोलन को उनके संघर्ष जो समुदाय नियंत्रित जैव विविधता पर आधारित खाद्य व्यवस्था विकसित करने के लिए चलाये जाते हैं में मदद करता है। 'अगेंस्ट द ग्रेन' हालिया ट्रेंड और इस दिशा में हुए विकास जिसपर ग्रेन काम करता है से जुड़े मसलों का छोटे-छोटे लेखों का विचार संग्रह है। ये सभी लेख विषेष और समसामयिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

अगेंस्ट द ग्रेन का संपूर्ण संग्रह को हमारे वेबसाईटः
www.grain.org/article/categories/13-against-the-grain
पर भी देखा जा सकता है।

ग्रेन,
गिरोना, 25 पीआरएएल., बार्सीलोना, स्पेन
टेली: 34 93 3011381, फैक्स: 34 933011627
ई मेलः grain@grain.org
_www.grain.org